आकाशवाणी शिमला

25.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

बजट सत्र

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की टैक्सियों व एल.एम.वी. पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के जिन लोगों का हर रोज आना जाना रहता है उन लोगों को पास जारी करने को लेकर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट टैग से एंट्री टैक्स को जोड़ने से दरें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हर चीज में राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एंट्री टैक्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है और अभी इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो टैक्स बढ़ाया है वो एनएचआईए के नियमों के मुताबिक फास्टैग के साथ जोड़ा गया है।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की है। दिल्ली से लौटते ही आज शिमला में उन्होंने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की और केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली जाकर पैसा रुकवाने के सुक्खू सरकार के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात है और मुख्यमंत्री अगर उनसे समय मांगेंगे तो उनसे भी मिलेगा।

वित्त विधेयक

लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त वर्ष 2026–2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों – एमएसएमई, किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि ये रोजगार सृजन, उत्पादन और देश के समग्र विकास के केंद्र में हैं। वित्तमंत्री ने बताया कि यह वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कुल 14 हजार 3 सौ 97 सरकारी स्कूलों में से केवल 8 हजार 9 सौ 10 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सुरेश कश्यप ने कहा कि डिजिटल शिक्षा आज की आवश्यकता है और हिमाचल के बच्चों को इससे वंचित रखना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश के बच्चों को डिजिटल शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

गैस आपूर्ति

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देशभर में घरेलू रसोई गैस की बुकिंग में भारी उछाल देखा जा रहा है। प्रदेश में फरवरी महीने की अपेक्षा मार्च में सामान्य से लगभग 35 फीसदी अधिक बुकिंग हुई है जिस वजह से कमर्शियल सिलेंडर की कमी भी हुई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के हिमाचल प्रमुख मोहम्मद आमीन ने बताया कि हिमाचल में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति भी सामान्य रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सरकार के निर्देशानुसार 20 फीसदी की जा रही है जिसे आगामी एक दो दिनों में 50 तक बढ़ा दिया जाएगा।